

प्रेषक,

एन0एस0नपलव्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2007

विषय:— मै0 एरोमा काफ्ट एण्ड टिशु प्रा0लि0 को औद्योगिक प्रयोजन हेतु तहसील रुड़की के ग्राम नूरपुर में कुल 1.900 है0 भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-278/भूमि व्यवस्था-भू0क0 दिनांक 7-4-2007 के सन्दर्भ में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 एरोमा काफ्ट एण्ड टिशु प्रा0लि0 को औद्योगिक प्रयोजन हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(V) के अन्तर्गत तहसील रुड़की ग्राम नूरपुर में कुल 1.900 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बंधक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उससे बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

.....(2)

१

गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी। उक्त अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना होगा।

7- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)-2005 के अंतर्गत GIDCR-2005 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

8- क्रय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- प्रस्तावित इकाई का निर्माण कार्य सीडा से ले-आउट स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10- प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र एरोमा कापट एण्ड टिशु प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित क्रिया कलापों की स्थापना हेतु किया जायेगा।

12- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पाट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

13- इकाई में पूंजी निवेश से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण तथा अग्निशमन आदि विभागों से नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

14- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि कय की व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है। औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने पर रुसंगत नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

15- उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरसत कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(एन0एस0नपलख्याल)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- श्री राजीव कुमार, डायरेक्टर, मै0 एरोमा क्राफ्ट एण्ड टिशु प्रा0िल0, 2 रेन्चो विहार, मारुती रोड मुज्जफरनगर।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(सन्तोष बडोनी)  
अनुसचिव।